मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) चट्टोपाध्याय आयोग ने 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में 138 सिफारिशें की गई थीं, जिसमें से अधिकांश सिफारिशें विस्तृत अध्ययन के अनुसार थीं। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक मौखिक पाठ्यक्रम तैयार करने, व्यावसायीकरण, प्रारम्भिक शिक्षा को संबसुलभ बनाने, शिक्षकों के स्तर, कार्य दशाओं तथा उनके कल्याण आदि से संबंधित थीं। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना (यथा संशोधित 1992) दोनों के निर्धारण में इन सिफारिशों पर पहले से ही ध्यान दे रही है तथा इस समय ने शिक्षकों से संशोधित वेतनमानों तथा उनकी परिलब्धियों को 1-1-1986 से अधिसूचना कर दी है। ऐसी स्थिति में इस समय अन्य राष्ट्रीय शिक्षक आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Schemes for development of children

6129. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whethtr schemes are being undertaken by Government for the development of children in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what steps have been taken by Government to check child mortality in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SMT. BASAVA RAJESHWARI): (a) and (b) The Major Schemes undertaken by Government for the development of children in the country include Integrated Child Development Services including Adolescent Girls Schtmes, Balwadi Nutrition Programme, Early Childhood Education and Creche/Day Care Centres for children of Working and ailing mothers as well as schemes for the welfare of Street Children and Prevention and Control of Juvenile Maladjustment and Child labour. Recently, a National Creche Fund for Child Care Services has also been set up.

(c) In addition to services being provided for mother and child development under ICDS and other child care programmes mentioned above, the Child Survival and Safe Motherhood Programme has been launched with a view to check child mortality in the country.

Multi cultural centres in Punjab

6130. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set up multi-cultural centres in the country particularly in the State of Punjab;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE (KUMARI SELJA): (a) to (c) A Scheme to set up Multipurpose Cultural Complexes in States, inculding those for children has been circulated to all States and Union Territories inviting proposals for financial assistance. No. proposal has been received from the Government of Punjab.

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) द्वारा उच्चस्तरीय प्रबंध समिति के सदस्यों की नियुक्ति

6131. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बाल्को) द्वारा किसी उच्चस्तरीय प्रबन्ध समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति में नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति की अवधि कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि मुख्य प्रबंध-निदेशक ने एक ऐसे व्यक्ति को इस समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, जिसे कम्पनी के कार्यकरण के बारे में कोई संगतपूर्ण जानकारी नहीं है;

(घ) यदि हां, तो किसके निर्देश पर ऐसे व्यक्ति को कम्पनी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है ; और

(ङ.) सरकार ने इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) चूंकि निदेशक (प्रचालन) सेवा निवृत्त हो चुके थे व ग्रुप महाप्रबंधक (वर्क्स) की उन्नति हो गयी थी अतः वर्ष 1993 में, कोरबा स्थित इकाई में एक प्रबंध समिति का गठन किया गया था तथा प्रशासनिक व वित्तीय मामलों पर तुरंत निर्णय लेने के लिए निदेशक (प्रचालन) के अधिकार इस समिति को हस्तांतरित कर दिए गए थे ।

(ख) समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :—

1. श्री पी०एन० शर्मा, महाप्रबंधक (वर्क्स)
2. श्री आर०एन० झा, महाप्रबंधक (भंडारन)
3. श्री वी०के० शर्मा, महाप्रबंधक (पीएंडए)

सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गयी थी । समिति ने 18 जनवरी, 1993 से 31 अक्टूबर, 1993 तक कार्य किया ।

(ख) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ.) बाल्को के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक द्वारा समिति का गठन किया गया था ।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां

6132. श्री अजीत जोगी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० द्वारा क्षेत्र के स्थानीय लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में बालाघाट और बिलासपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों को नौकरियों उपलब्ध कराने के लिए कोई कक्ष स्थापित किए जाने का विचार है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित जिन लोगों को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) भारत एल्यूमिनियम कंपनी खुले विज्ञापन के द्वारा अखिल भारतीय आधार पर, अधिकारी वर्ग के पदों के लिए नियुक्ति करती है । कर्मचारी वर्ग की सभी नियुक्तियां कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही होती हैं इसके लिए यह आवश्यक है कि सिर्फ वे उम्मीदवार, जिन्हें स्थानीय रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित किया गया है, उनकी उपयुक्तता व अन्य निर्धारित मानदंडों को देखते हुए रोजगार/नियुक्ति देने के लिए सिर्फ उन्हीं के नामों पर विचार किया जाए ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों का विवरण नीचे दिया गया है ।